इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. बनाम पोंटी मलिक निर्माण कंपनी और अन्य

(अनिल क्षेत्रपाल, जे.)

अनिल क्षेत्रपाल जे. के समक्ष

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ---------- याचिकाकर्ता

बनाम

पोंटी मलिक कंस्ट्रक्शन कंपनी और एक अन्य ---------- प्रतिवादी

सी□ र नंबर 3214 ऑफ 2017

19 अप्रैल, 2018

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996- एस.एस. 14(2) और 15(2) - मध्यस्थ के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा □ वेदन को खारिज करने को चुनौती, जिसमें मध्यस्थ से खुद को एकमात्र मध्यस्थ के कार्यालय से अलग करने का अनुरोध किया गया है - अधिनियम की धारा 14 और धारा 15 के दायरे में कोई □ धार नहीं है - इसलिए, याचिका खारिज।

माना गया कि वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 15(2) के साथ पठित धारा 14(2) के तहत एक □ वेदन दायर किया था। इस न्यायालय की सुविचारित राय में, याचिकाकर्ता कोई भी □ धार सामने लाने में विफल रहा जो अधिनियम की धारा 14 और धारा 15 के दायरे में □ सकता है। धारा 14 केवल दो घटनाओं से संबंधित है जैसा कि अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (ए) और खंड (बी) के तहत प्रदान किया गया है। अधिनियम की धारा 14(2) धारा 14(1) के केवल खंड (ए) से संबंधित है जो यह प्रावधान करता है कि यदि मध्यस्थ कानूनी रूप से या अपने कार्यों को करने में असमर्थ है या अन्य कारणों से बिना किसी अनुचित देरी के कार्य करने में विफल रहता है। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता उस □ धार को इंगित करने में विफल रहा है जो अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (1) के खंड (ए) के अंतर्गत □ सकता है।

(पैरा 16)

इसके अलावा, धारा 15 दो अलग-अलग घटनाओं से संबंधित है, एक यह है कि जब मध्यस्थ किसी भी कारण से कार्यालय से हट जाता है; या पार्टियों के समझौते के अनुसार, मध्यस्थ को प्रतिस्थापित किया जाना है। वर्तमान मामले में, अधिनियम की धारा 15 द्वारा परिकल्पित किसी भी घटना को इंगित नहीं किया गया है।

(पैरा 17)

□ र.के. छिब्बर, वरिष्ठ अधिवक्ता, अभिनव टंडन, अधिवक्ता के साथ याचिकाकर्ता के लिए

अनमोल प्रताप सिंह मान, वकील, प्रतिवादी संख्या 1 के लिए

अनिल क्षेत्रपाल, जे. (मौखिक)

(1) याचिकाकर्ता-इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत यह पुनरीक्षण याचिका दायर की है, जिसमें दिनांक 11.02.2014 के □ देश को चुनौती दी गई है, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 14(2) और 15(2) के तहत दायर एक □ वेदन को खारिज कर दिया गया है। (इसके बाद इसे 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया जाएगा)। यह पुनरीक्षण याचिका 2 साल से अधिक की देरी के बाद दायर की गई थी।

(2) प्रतिवादी-कंपनी को पानीपत रिफाइनरी में कच्चे जल भंडार चैनल और पंप हाउस के निर्माण का ठेका दिया गया था। पक्षों के बीच समझौते में विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थता खंड शामिल था। प्रतिवादी-ठेकेदार ने अधिनियम की धारा 11 के तहत एक □ वेदन दायर किया और विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, पानीपत ने उड़ीसा में स्थित लोक निर्माण विभाग के सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता श्री अजीत कॉमर रॉय को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में को नियुक्त किया हैं। विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा पारित □ देश को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, लेकिन बाद में संशोधन को मध्यस्थ के समक्ष पार्टियों के बीच किसी भी विवाद की गैर-मौजूदगी और सीमा का सवाल उठाने की स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया गया था। यहां तक कि याचिकाकर्ता द्वारा एक समीक्षा □ वेदन भी दायर किया गया था, जिसका निस्तारण याचिकाकर्ता को मध्यस्थ के समक्ष ही मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने की अनुमति देकर कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित □ धारों पर कार्यवाही को चुनौती देते हुए विद्वान मध्यस्थ के समक्ष अधिनियम की धारा 16(2) के साथ पठित धारा 16(5) के तहत एक □ वेदन दायर किया: -

(i) मध्यस्थ के रूप में श्री अजीत कुमार रॉय की नियुक्ति का औचित्य;

(ii) मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व; और

(iii) किसी भी अधिसूचित दावे का अस्तित्व (जीसीसी के खंड 6.6.3.0 के प्रावधानों के अनुसार अंतिम विधेयक में शामिल एक अधिसूचित दावा तो दूर) ताकि प्रतिवादी के दावों को मध्यस्थता समझौते के दायरे में लाया जा सके। जीसीसी के खंड 9.0.1.0 या एलडी मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र में सन्निहित।"

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. बनाम पोंटी मलिक निर्माण कंपनी और अन्य

(अनिल क्षेत्रपाल, जे.)

(3) एकमात्र मध्यस्थ ने दिनांक 29.12.2006 के देश द्वारा वेदन को खारिज कर दिया। तत्पश्चात, विद्वान मध्यस्थ ने मध्यस्थता कार्यवाही को गे बढ़ाया। एक बार फिर से मध्यस्थ को एक और वेदन किया गया और विद्वान मध्यस्थ ने 09.05.2007 को एक देश पारित किया, जिसका ऑपरेटिव भाग इस प्रकार है: -

> "विवाद का निर्णय कि क्या दावेदार का प्रत्येक दावा मध्यस्थता खंड और अनुबंध के प्रासंगिक खंडों के संबंध में स्वीकार्य है, समझौते के प्रासंगिक खंडों की जांच और उचित व्याख्या पर निर्भर है। इसलिए, पार्टियों को योग्यता के धार पर कार्यवाही की सुनवाई के दौरान दावेदार के प्रत्येक दावे के संबंध में अपनी संबंधित सामग्री, दस्तावेज, साक्ष्य और उनके संबंधित तर्क रखने का अवसर दिया गया है।

(4) इसके बाद, याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 13 के तहत एक वेदन दायर किया, जिसमें अनुरोध किया गया कि वह कार्यवाही में एकमात्र मध्यस्थ के कार्यालय से खुद को अलग कर ले या वैकल्पिक रूप से एकमात्र मध्यस्थ के रूप में अपने कार्यालय में बने रहने की चुनौती पर निर्णय ले। उक्त वेदन में बताए गए धार पर विद्वान मध्यस्थ ने इस प्रकार रिकॉर्डिंग करते हुए वेदन का निपटारा किया: -

> "इसलिए, गे की कार्यवाही के संचालन के लिए, मैं देश देता हूं कि दावेदार को मध्यस्थता समझौते और अनुबंध खंडों के संदर्भ में अपने प्रत्येक दावे की मध्यस्थता को प्रमाणित करने के लिए अपने साक्ष्य रखने होंगे।"

(5) इसके बाद भी याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 14(1)(ए) के तहत एकमात्र मध्यस्थ को नोटिस देकर अनुरोध किया कि वह मध्यस्थता में गे न बढ़ें क्योंकि उसका जनादेश समाप्त हो चुका है।

(6) याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 14(2) और 15(2) के तहत विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, पानीपत के समक्ष मध्यस्थता मामला संख्या 1/2008 दायर किया, जिसे खारिज कर दिया गया है, जो वर्तमान याचिका पुनरीक्षण में चुनौती का विषय है।

(7) इस न्यायालय ने पक्षों के विद्वान वकीलों की दलीलों को विस्तार से सुना है और उनकी सक्षम सहायता से समय-समय पर विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित देशों और विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, पानीपत द्वारा पारित देश का पालन किया है।

(8) अधिनियम की धारा 5 में प्रावधान है कि कोई भी न्यायिक प्राधिकारी हस्तक्षेप नहीं करेगा, सिवाय इसके कि जहां ऐसा प्रावधान किया गया हो। दूसरे शब्दों में, मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही में न्यायिक हस्तक्षेप का दायरा बहुत सीमित है और केवल उन मामलों में ही प्रतिबंधित है जहां अधिनियम में ऐसा प्रदान किया गया है।

(9) अधिनियम की धारा 11 उप-धारा 6 कुछ निश्चित परिस्थितियों में मध्यस्थ के परिवर्तन/प्रतिस्थापन/नियुक्ति की प्रक्रिया से संबंधित है। याचिकाकर्ता का मामला यह नहीं है कि उसका मामला अधिनियम की धारा 11(6) के तहत प्रदान की गई घटनाओं में पड़ता है।

(10) अधिनियम की धारा 13 उप-धारा 5 में प्रावधान है कि जब भी उप-धारा (4) के तहत एक मध्यस्थ पुरस्कार दिया जाता है, तो मध्यस्थ को चुनौती देने वाला पक्ष धारा 34 के अनुसार ऐसे मध्यस्थ पुरस्कार को अलग करने के लिए वेदन कर सकता है। अधिनियम। धारा 13 चुनौती प्रक्रिया से संबंधित है।

(11) अधिनियम की धारा 14 एक पक्ष को अधिनियम की धारा 14 के खंड (ए) में निर्दिष्ट धार पर जनादेश की समाप्ति पर निर्णय लेने के लिए न्यायालय में वेदन करने में सक्षम बनाती है, वर्तमान मामले में, वेदन धाराओं के तहत दायर किया गया था अधिनियम की धारा 14(2) और 15(2)। संदर्भ की सुविधा के लिए, अधिनियम की धारा 14 और 15 निम्नानुसार निकाली गई हैं: -

> **14. कार्य करने में विफलता या असंभवता**.-- (1) एक मध्यस्थ का अधिदेश समाप्त हो जाएगा यदि—
>
> (ए) वह अपने कार्यों को करने में कानूनी या वास्तविक रूप से असमर्थ हो जाता है या अन्य कारणों से बिना किसी देरी के कार्य करने में विफल रहता है; और
>
> (बी) वह अपने कार्यालय से हट जाता है या पार्टियां उसके जनादेश को समाप्त करने के लिए सहमत हो जाती हैं।
>
> (2) यदि उप-धारा (1) के खंड (ए) में निर्दिष्ट किसी भी धार पर कोई विवाद बना रहता है, तो एक पक्ष, जब तक कि पार्टियों द्वारा अन्यथा सहमति न हो, जनादेश की समाप्ति पर निर्णय लेने के लिए न्यायालय में वेदन कर सकता है।.
>
> (3) यदि, इस धारा या धारा 13 की उपधारा (3) के तहत, कोई मध्यस्थ अपने कार्यालय से हट जाता है या कोई पक्ष मध्यस्थ के देश को समाप्त करने के

लिए सहमत होता है, तो इसका मतलब किसी भी धार की वैधता की स्वीकृति नहीं होगी इस खंड या धारा 12 की उपधारा (3) में संदर्भित।

15. अधिदेश की समाप्ति और मध्यस्थ का प्रतिस्थापन -- (1) धारा 13 या धारा 14 में निर्दिष्ट परिस्थितियों के अलावा, मध्यस्थ का अधिदेश समाप्त हो जाएगा—

(ए) जहां वह किसी भी कारण से पद से हट जाता है; या

(बी) पार्टियों के समझौते के अनुसार या उसके अनुसार।

(2) जहां एक मध्यस्थ का जनादेश समाप्त हो जाता है, एक स्थानापन्न मध्यस्थ को उन नियमों के अनुसार नियुक्त किया जाएगा जो प्रतिस्थापित किए जा रहे मध्यस्थ की नियुक्ति पर लागू थे।

(3) जब तक पार्टियों द्वारा अन्यथा सहमति न दी जाए, जहां उप-धारा (2) के तहत एक मध्यस्थ को प्रतिस्थापित किया जाता है, तो पहले हुई किसी भी सुनवाई को मध्यस्थ न्यायाधिकरण के विवेक पर दोहराया जा सकता है।

(4) जब तक पार्टियों द्वारा अन्यथा सहमति न हो, इस धारा के तहत मध्यस्थ के प्रतिस्थापन से पहले दिया गया मध्यस्थ न्यायाधिकरण का देश या निर्णय केवल इसलिए अमान्य नहीं होगा क्योंकि मध्यस्थ न्यायाधिकरण की संरचना में बदलाव हु है।

(12) न्यायिक हस्तक्षेप और ऐसे न्यायिक हस्तक्षेप का दायरा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **एम/एस एस.बी.पी. एंड कंपनी बनाम एम/एस। पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड एवं Anr.1.** के मामले में निर्णायक रूप से निर्धारित किए गए चरण पर होना चाहिए। उपरोक्त निर्णय के पैराग्राफ 45, 46 और 47, जो मामले के निर्णय के लिए प्रासंगिक हैं, निम्नानुसार निकाले गए हैं: -

45. यह देखा गया है कि कुछ उच्च न्यायालय इस धार पर गे बढ़े हैं कि मध्यस्थता के दौरान मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित कोई भी देश, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 या 227 के तहत चुनौती देने में सक्षम होगा। हमें इस तरह के दृष्टिकोण का कोई औचित्य नहीं दिखता। धारा 37 मध्यस्थ न्यायाधिकरण के कुछ देशों को अपील योग्य बनाती है। धारा 34 के तहत, पीड़ित पक्ष के पास अधिनियम की धारा 16 के तहत कार्य करने वाले मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित किए गए किसी भी बीच के देश सहित पुरस्कार के खिलाफ अपनी शिकायतों को व्यक्त करने का एक अवसर है। मध्यस्थ न्यायाधिकरण के किसी भी देश से पीड़ित पक्ष को, जब तक कि अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील का अधिकार न हो, न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय पारित होने तक इंतजार करना पड़ता है। यह अधिनियम की

योजना प्रतीत होती है। मध्यस्थता न्यायाधिकरण ख़िरकार, पार्टियों के बीच एक अनुबंध का प्राणी है, मध्यस्थता समझौता, भले ही यदि अवसर ता है, तो मुख्य न्यायाधीश पार्टियों के बीच अनुबंध के धार पर इसका गठन कर सकते हैं। लेकिन इससे मध्यस्थ न्यायाधिकरण की स्थिति में कोई बदलाव नहीं एगा. यह अभी भी पार्टियों द्वारा सहमति से चुना गया एक मंच होगा। इसलिए, हम कुछ उच्च न्यायालयों द्वारा अपनाए गए इस रुख को अस्वीकार करते हैं कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित कोई भी देश भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 या 227 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा सही किए जाने में सक्षम है। उच्च न्यायालयों द्वारा इस तरह का हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं है।

46. जब मामला मध्यस्थता की प्रक्रिया में हो तो न्यायिक हस्तक्षेप को कम करने का उद्देश्य निश्चित रूप से विफल हो जाएगा यदि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रत्येक के खिलाफ उच्च न्यायालय से संपर्क किया जा सकता है। मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया देश. इसलिए, यह इंगित करना वश्यक है कि एक बार मध्यस्थ न्यायाधिकरण में मध्यस्थता शुरू हो जाने के बाद, पार्टियों को पुरस्कार सुनाए जाने तक इंतजार करना होगा, जब तक कि निश्चित रूप से, अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील का अधिकार उनके लिए पहले अवस्था से भी उपलब्ध न हो।

47. इसलिए, हम अपने निष्कर्षों को इस प्रकार सारांशित करते हैं:

(i) अधिनियम की धारा 11(6) के तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयोग की गई शक्ति एक प्रशासनिक शक्ति नहीं है। यह एक न्यायिक शक्ति है.

(ii) अधिनियम की धारा 11(6) के तहत शक्ति, पूरी तरह से, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा केवल उस न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश को और भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किसी अन्य न्यायाधीश को सौंपी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट।

(iii) उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पदनाम के मामले में, नामित न्यायाधीश द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति क़ानून द्वारा प्रदत्त मुख्य न्यायाधीश की होगी।

(iv) मुख्य न्यायाधीश या नामित न्यायाधीश को प्रारंभिक पहलुओं पर निर्णय लेने का अधिकार होगा जैसा कि इस निर्णय के पहले भाग में दर्शाया गया है। ये उसका अपना अधिकार क्षेत्र होगा, अनुरोध पर विचार करने के लिए, एक वैध मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व, एक जीवित दावे का अस्तित्व या अन्यथा, उसकी शक्ति के प्रयोग के लिए शर्तों का अस्तित्व और मध्यस्थ या मध्यस्थों की योग्यता पर। □ वश्यकता पड़ने पर मुख्य न्यायाधीश या नामित न्यायाधीश अधिनियम की धारा 11(8) के संदर्भ में योग्य मध्यस्थ को नामित करने के मामले में किसी संस्था की राय लेने के हकदार होंगे, लेकिन मध्यस्थ की नियुक्ति का □ देश केवल यही हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश या नामित न्यायाधीश का.

(v) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अधिनियम की धारा 11(6) के तहत प्राधिकारी के रूप में जिला न्यायाधीश का पदनाम अधिनियम की योजना पर □ धारित नहीं है।

(vi) एक बार जब मामला मध्यस्थ न्यायाधिकरण या एकमात्र मध्यस्थ के पास पहुंच जाता है, तो उच्च न्यायालय मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान मध्यस्थ या मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित □ देशों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और पक्ष केवल धारा के संदर्भ में अदालत से संपर्क कर सकते हैं। अधिनियम की धारा 37 या अधिनियम की धारा 34 के संदर्भ में।

(vii) चूंकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उस न्यायालय के नामित न्यायाधीश द्वारा पारित □ देश एक न्यायिक □ देश है, इसलिए उस □ देश के खिलाफ भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है।

(viii) अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत किसी □ वेदन पर विचार करते समय भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के □ देश के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती है।

(ix) ऐसे मामले में जहां पार्टियों द्वारा अधिनियम की धारा 11(6) का सहारा लिए बिना एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन किया गया है, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास अधिनियम की धारा 16 के अनुसार सभी मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र होगा।

(x) चूंकि सभी कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा निर्देशित थे। वी. रानी कंस्ट्रक्शन प्रा. लिमिटेड और अधिनियम की धारा 11(6) के तहत □ देश उस निर्णय में अपनाई गई स्थिति के □ धार पर किए गए हैं, हम स्पष्ट करते हैं कि अब तक की गई मध्यस्थों या मध्यस्थ न्यायाधिकरणों की नियुक्तियों को वैध माना जाएगा, सभी □ पत्तियों को उन पर छोड़ दिया जाएगा अधिनियम की धारा 16 के तहत निर्णय लिया जाए। इस तिथि से, इस निर्णय में अपनाई गई स्थिति अधिनियम की धारा 11(6) के तहत लंबित □ वेदनों को भी नियंत्रित करेगी।

(xi) जहां जिला न्यायाधीशों को अधिनियम की धारा 11(6) के तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित किया गया था, उनके द्वारा अब तक किए गए नियुक्ति □ देश वैध माने जाएंगे; लेकिन यदि इस तिथि तक उनके समक्ष कोई □ वेदन लंबित है तो उसे संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित उस न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा निपटाए जाने के लिए स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

(xii) कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य में निर्णय। वी. रानी कंस्ट्रक्शन प्रा. लिमिटेड को खारिज कर दिया गया है

(13) अब प्रश्न यह उठता है कि क्या उच्च न्यायालय को इस स्तर पर मध्यस्थता कार्यवाही में हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं?

(14) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण के किसी भी □ देश से पीड़ित पक्ष को, जब तक कि अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अधिकार न हो, धारा 34 के तहत कार्यवाही में पूर्वोक्त □ देश को चुनौती देने के लिए इंतजार करना होगा। कार्यवाही करना। न्यायालय ने यह भी देखा है कि उच्च न्यायालय भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए प्रत्येक □ देश के खिलाफ हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

(15) एक ओर, याचिकाकर्ता का दावा है कि विवाद मध्यस्थता योग्य नहीं है क्योंकि दावा अधिसूचित दावे के दायरे में नहीं □ ता है और इसलिए मध्यस्थता समझौते के दायरे से बाहर है। जबकि दूसरी ओर, प्रतिवादी का दावा है कि विवाद मध्यस्थता योग्य है।

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. बनाम पोंटी मलिक निर्माण कंपनी और अन्य
(अनिल क्षेत्रपाल, जे.)

(16) वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 15(2) के साथ पठित धारा 14(2) के तहत एक वेदन दायर किया था। इस न्यायालय की सुविचारित राय में, याचिकाकर्ता कोई भी धार सामने लाने में विफल रहा जो अधिनियम की धारा 14 और धारा 15 के दायरे में सकता है। धारा 14 केवल दो घटनाओं से संबंधित है जैसा कि धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (ए) और खंड (बी) के तहत प्रदान किया गया है। धारा 14(2) धारा 14(1) के केवल खंड (ए) से संबंधित है। अधिनियम जो यह प्रावधान करता है कि यदि मध्यस्थ कानूनी या वास्तविक रूप से अपने कार्यों को करने में असमर्थ है या अन्य कारणों से बिना किसी अनुचित देरी के कार्य करने में विफल रहता है। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता उस धार को इंगित करने में विफल रहा है जो धारा 14 की उप-धारा (1) के खंड (ए) के अंतर्गत सकता है।

(17) धारा 15 दो अलग-अलग घटनाओं से संबंधित है, एक यह है कि जब मध्यस्थ किसी भी कारण से कार्यालय से हट जाता है; या पार्टियों के समझौते के अनुसार, मध्यस्थ को प्रतिस्थापित किया जाना है। वर्तमान मामले में, अधिनियम की धारा 15 द्वारा परिकल्पित किसी भी घटना को इंगित नहीं किया गया है।

(18) उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, इस न्यायालय को विद्वान न्यायालय द्वारा पारित देश में हस्तक्षेप करने का कोई अच्छा धार नहीं मिलता है।

(19) पुनरीक्षण याचिका खारिज की जाती है।

अस्विकरण- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उदेश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी वयावहारिक और अधिकारिक उदेश्यके लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रारंभिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य के लिए उपयुकत रहेगा।

संगीता ट्रांस्लेटर